



दी नैक्सट पोस्ट

साप्ताहिक

7 सदन में पेश किया गया आठ लाख आठ हजार 736 करोड़ का बजट 5 गन्ना किसानों को राहत 8 स्वर्ण पदक जीतने में रहे सफल

UPHIN51019

वर्ष: 02, अंक: 35

पृष्ठ संख्या: 8

मूल्य: 1.00 रु.

सोमवार 24 फरवरी, 2025

आवास एवं शहरी नियोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली-गाजियाबाद मेट्रो कॉरिडोर संचालित है।

सम्पूर्ण कॉरिडोर का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूरा किये जाने का अनुमान है।

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउन शिप विकसित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरणधन्ये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये स्टेट कैपिटल रीजन गठित किये जाने तथा अन्य रीजन के रीजनल प्लान तैयार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 प्रख्यापित है।

स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमशः लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित हैं।

अभिषेक हत्याकांड-फरार मानवेंद्र सिंह ने देवरिया न्यायालय में किया सरेंडर



गोरखपुर। वर्ष 2019 में दर्ज हुए आर्मस एक्ट के मुकदमे में जमानत वापस कराकर मानवेंद्र सिंह ने सरेंडर किया है। इस हत्याकांड में तीन लोग आरोपी बनाए गए थे। दो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि तीसरे ने बृहस्पतिवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। गोरखपुर के बेलघाट में अभिषेक सिंह हत्याकांड के फरार आरोपी मानवेंद्र सिंह ने देवरिया को में आत्मसमर्पण कर दिया। 2019 के एक आर्मस एक्ट मामले में मानवेंद्र ने सरेंडर किया है। इसके पहले बुधवार की रात में दूसरे आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में मानवेंद्र के साथ कुछ और लोग भी नामजद थे। मामले में मिली जमानत को निरस्त करवा कर मानवेंद्र सिंह ने सरेंडर किया है। इससे पहले, मानवेंद्र सिंह के पहले बिक्कू सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

योगी सरकार ने खोला पिटारा

यूपी की मेधावी छात्राओं के लिए किया ये बड़ा एलान

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। वहीं, विन्ध्यांचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणधीन भवनों को पूर्ण किये जाने के लिए 52 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई।



यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जानिए खास बातें

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

वर्तमान व आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाये। वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही है। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रदेश में विज्ञान पार्क, साईंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा को लेकर बजट में क्या ?

प्रदेश में डिप्लोमा स्वीयर 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणधीन हैं। राजकीय पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है। राजकीय पालीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नतन (सेन्टर आफ एक्सिलेंस) की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पालीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस शिक्षा हेतु सेन्टर अफ एक्सिलेंस की स्थापना के लिये 1 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दो फ्री सिलिंडर छात्राओं को स्कूटी

स्मार्ट सिटी बनेंगी 58 पालिका

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 9वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े एलान किए हैं। यूपी सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देगी। युवाओं को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। चार नए एक्सप्रेसवे का एलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।

यूपी बजट में तोहफा

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है प्रदेश में विकास कार्य हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। क्रिटिकल मैस योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थित जनपदों के अन्तर्देशीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ रुपये तथा 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।



दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की नई टीम मंत्री बनें छह विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ छह मंत्रियों ने भी शपथ ली। उप राज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि दिल्ली के सीएम की दौड़ में प्रवेश वार्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, शिवा राय समेत कई चेहरों का नाम लिया जा रहा था। आखिरकार बाजी रेखा गुप्ता ने मारी। वे हैं वो छह नाम जो बने मंत्री दिल्ली की नई सरकार के शपथग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ छह मंत्री भी शपथ ली। प्रवेश वार्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बने।

सीट पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाने वाले प्रदेश वार्मा सीएम की रस में सबसे आगे थे।

- कपिल मिश्रा कपिल मिश्रा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया गया कयावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कयावल नगर से दूसरी बार जीत हासिल की है। भाजपा से पहले वह आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं।
- आशीष सूद रेखा गुप्ता के साथ आशीष सूद ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। आशीष सूद जनकपुरी से चुनाव जीते हैं। वे पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले आशीष पार्षद रहे हैं। वे भाजपा के गोवा व जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। सूद पंजाबी समाज से आते हैं। प्रदेश भाजपा नेतृत्व भी पंजाबी समाज से ही है।
- मनजिंदर सिंह सिरसा मनजिंदर सिंह सिरसा को भी दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल किया

गया। वह राजीव गाईन से विधायक हैं। तीसरी बार विधायक बने सिरसा दिल्ली में भाजपा का सिख चेहरा हैं। साल 2021 में मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल से भाजपा में शामिल हुए थे।

- पंकज सिंह विकासपुरी से जीत हासिल करने वाले विधायक पंकज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पंकज सिंह हरियाणा के गोवा व जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। सूद पंजाबी समाज से आते हैं। प्रदेश भाजपा नेतृत्व भी पंजाबी समाज से ही है।
- रविंद्र इंद्राज रेखा गुप्ता के साथ रविंद्र इंद्राज भी शपथ ली। उनका नाम भी मंत्री पद की शपथ लेने वालों में शामिल है। वह बवाना सुबित सीट से पहली बार विधायक बने हैं।

सम्पादकीय

ट्रम्प का भारत विरोधी रवैया साफ

डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद सम्हाले हुए अभी एक ही माह हुआ है और उनका भारत विरोधी रवैया साफ हो चुका है और उनका भारत विरोधी रवैया साफ हो चला है

डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद सम्हाले हुए अभी एक ही माह हुआ है और उनका भारत विरोधी रवैया साफ हो चला है। अमेरिका की ओर से भारत का सतत अपमान तो हो ही रहा है, अब उसकी मदद रोककर यह संकेत दे दिया गया है कि अमेरिका के भारत के साथ वैसे सम्बन्ध नहीं रहेंगे जैसे पहले कभी होते थे। अधिक अपमानजनक तो यह है कि अमेरिका के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के लिये भारत लगातार झुकता चला जा रहा है और अमेरिका है कि नरम पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह एक के बाद एक भारत विरोधी निर्णय लेता जा रहा है।

भारत को लेकर ट्रम्प का रुख वैसे तभी स्पष्ट हो गया था जब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया था। उनकी बजाये उद्योगपति मुकेश अंबानी को सपत्नीक तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर को आमंत्रित कर एक तरह से मोदी का अपमान ही किया गया था। वैसे बताया जाता है कि जयशंकर को कुछ दिनों तक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में डेरा डालना पड़ा था पर ट्रम्प ने भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया सो नहीं ही बुलाया। इसके बाद भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ मुलाकात को लालायित मोदी ने अमेरिका का दौरा कर ही लिया। पिछले हफ्ते वे उनसे मिलकर आये हैं। ट्रम्प के साथ निजी मित्रता का दावा करने वाले मोदी जब अमेरिका जा रहे थे तभी अमेरिका ने पहली खेप के रूप में वहां रह रहे 104 गैरकानूनी अप्रवासी भारतीयों को सैन्य जहाज में हथकड़ी-बेड़ियों में बांधकर अमृतसर भेज दिया। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी इस बाबत कड़े शब्दों में न केवल विरोध जताएंगे वरन यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम अब आगे आने वाले भारतीय ऐसे अपमानजनक तरीके से नहीं भेजे जायेंगे।

वैसे पिछली बार अमेरिका ने जब इस तरह से भारतीयों को भेजा तब भारत में भारतीय जनता पार्टी व सरकार का एक बड़ा समर्थक वर्ग उस कार्रवाई को यह कहकर जायज ठहरा रहा था कि अमेरिका अपने देश के नियमों का पालन कर रहा है तो इसमें गलत ही क्या है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने भी संसद में इस पर अपना बयान देकर अमेरिका का समर्थन किया था। हालांकि उस वक्त यह बात भी सामने आई थी कि कोलम्बिया व मैक्सिको जैसे छोटे देश, जो अमेरिका के पड़ोसी भी हैं, अपने नागरिकों को सम्मानपूर्वक वापस लाए थे। अपने ही नागरिकों के प्रति भारत सरकार के इस रवैये से सम्भवतः ट्रम्प प्रशासन का हौसला बढ़ा होगा तभी उसने शनिवार की रात फिर से 116 भारतीय उसी तरीके से भेजे। जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका है कि अमेरिका ने ऐसे तकरीबन 18 हजार अवैध प्रवासियों की शिनाख्त कर ली है जो क्रमवार भारत आयेंगे। भारत की प्रतिष्ठा को किस कदर चोट पहुंचेगी और उसकी छवि दुनिया भर में क्या बनेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साफ है कि ट्रम्प इस मामले में भारत के साथ कोई रहमदिली नहीं दिखाने जा रहे हैं।

ट्रम्प मानों इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं जो उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली 21 मिलियन डॉलर की सहायता पर भी रोक लगा दी। दरअसल उन्होंने सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के फैंसले को मंजूरी दी है जिसने इस आशय की सिफारिश की है। एक प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि श्भारत के पास बहुत पैसा है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। अमेरिका के लिये वहां व्यवसाय करना मुश्किल है क्योंकि उसके शुल्क बहुत हैं। उनका कहना था कि भारत की आर्थिक वृद्धि तथा विदेशी व्यापार की ऊंची शुल्क दरों के चलते भारत को अमेरिकी करदाताओं का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि डीओजीई की अध्यक्षता दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी व ट्रम्प के नजदीकी एलन मस्क करते हैं। उन्होंने एक्स पर इस कटौती की घोषणा की जो भारत को बड़ा झटका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपने अमेरिकी दौरे पर मोदी मस्क से उनके परिजनों के साथ मिले थे और दोनों के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में चर्चा भी हुई थी। मस्क ने भारत के साथ लाइबेरिया में भी मतदाताओं का राजनीतिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने के सम्बन्धी गतिविधियों के लिये दी जाने वाली लगभग इतनी ही सहायता राशि तथा नेपाल को जैव विविधता के संरक्षण हेतु आवंटित किये जाने वाले धन को भी रोक दिया है। मस्क ने इन सभी को श्गौरजरूरी खर्च बतलाया है।

अमेरिका से मिल रहे ये सारे संकेत भारत के लिये बहुत बुरे कहे जा सकते हैं। ट्रम्प ने एक ओर तो मोदी से उस समझौते पर हस्ताक्षर करा लिये जिसके अंतर्गत भारत अमेरिका से प्राकृतिक गैस व तेल (जो कि महंगी दर पर होगा) तथा एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा, जो पुरानी पड़ चुकी तकनीक पर आधारित है व जिसे मस्क कबाड़ बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अमेरिकी कम्पनी टेस्ला की व्यवसायिक गतिविधियां प्रारम्भ होने जा रही हैं, जिसके मालिक एलन मस्क ही हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका भारत के साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। भारत को इसका कड़ा जवाब देने की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि देश में भाषा को लेकर इस तरह का विवाद पहली बार खड़ा हुआ है, यह सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। भाजपा के शासन के दौर में इसमें तल्खी थोड़ी और बढ़ गई है। बहरहाल, पहले देख लेते हैं कि श्री योगी ने उर्दू का विरोध करते हुए कैसे अपनी ही पोल खोल दी। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की हालत कितनी खराब है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। संपन्न ग्रामीण अपने बच्चों को शहरों में भेजकर पढ़ाने का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन गरीब ग्रामीणों के लिए गांव के विद्यालय में बच्चों को भेजने की मजबूरी होती है, जहां कई तरह के अभावों में बच्चों को पढ़ाने की औपचारिकता निभाई जाती है। सियासी लाभ उठाने के फेर में कभी-कभी मंजे हुए राजनेता भी ऐसी गलती कर जाते हैं, जिसमें सच बाहर आ जाता है। अभी हाल ही में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ऐसी ही गलती कर दी। दरअसल मंगलवार को उप्र विधानसभा में कार्य संचालन नियमावली में एक संशोधन के बाद अंग्रेजी के अलावा, अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में भी संबोधन को मान्यता दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि ग्रामीण अंचल के लोग अपनी स्थानीय भाषा में सुन सकें कि विधानसभा में क्या कार्रवाई हो रही है। इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने अंग्रेजी पर आपत्ति जताई और उसकी जगह उर्दू और संस्कृत शामिल करने का सुझाव दिया। लेकिन उर्दू का नाम आते ही यह मुद्दा भाजपा के लिए सांप्रदायिक सवाल खड़े करने का सबब बन गया। मंगलवार को उर्दू के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने जो कुछ कहा, उसमें एक तरफ उनकी संकुचित सोच का परिचय मिला और दूसरी तरफ एक सचबयानी भी हो गई। श्री योगी ने कहा कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूल में और दूसरों के बच्चों के लिए बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़ाओ, जहां संसाधन भी नहीं हैं। श्री योगी ने समाजवादियों पर आरोप लगाया कि ये आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपके बच्चे उर्दू पढ़ें ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। सपा के नेता क्या देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं यह नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि देश में भाषा को लेकर इस तरह का विवाद पहली बार खड़ा हुआ है, यह सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। भाजपा के शासन के दौर में इसमें तल्खी थोड़ी और बढ़ गई है। बहरहाल, पहले देख लेते हैं कि श्री योगी ने उर्दू का विरोध करते हुए कैसे अपनी ही पोल खोल दी। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की हालत कितनी खराब है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। संपन्न ग्रामीण अपने बच्चों को शहरों में भेजकर पढ़ाने का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन गरीब ग्रामीणों के लिए गांव के विद्यालय में बच्चों को भेजने की मजबूरी होती है, जहां कई तरह के अभावों में बच्चों को पढ़ाने की औपचारिकता निभाई जाती है। देश की साक्षरता दर में इजाफा होता है कि इस साल इतने बच्चों ने दाखिला लिया, हालांकि

इसमें कितने बच्चे विद्यालय में टिक पाते हैं, यह अलग मंथन का विषय है। इन स्कूलों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी अक्सर नहीं होती है, जिस वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। गांवों के स्कूलों की बदहाली किसी एक राज्य या किसी एक सरकार में हुई है, ऐसा नहीं है। पूरे देश में यही हाल है। लेकिन इस बात को सरकारें स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि कभी भूले-बिसरे किसी नेता, मंत्री या शिक्षा अधिकारी के दौरे स्कूलों में हों, तो वहां साज-सज्जा कर कमियां छिपाने की कोशिश की जाती है। मंत्री और अधिकारी दोनों इस सच से वाकिफ होते हैं, लेकिन इसे सुधारने की कोशिश बिरले ही किसी ने की

उर्दू पर संकीर्ण सोच

होगी। अच्छा है कि मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में आधिकारिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली कि गांवों के स्कूलों में संसाधन नहीं हैं। अब उनसे सवाल किया जा सकता है कि आप लगातार दूसरा कार्यकाल उत्तरप्रदेश में संभाल रहे हैं, फिर भी अगर आप गांवों के स्कूलों में संसाधन न होने की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें दोष क्या आपका ही नहीं है। जब उप्र सरकार अयोध्या में हर साल करोड़ों रूपए के दिए जला सकती है, जब महाकुंभ के आयोजन में पानी की तरह पैसा बहाया जा सकता है, जब कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का खर्च भी सरकारी खजाने से किया जा सकता है, तो गांवों के स्कूलों में संसाधन जुटाने का खर्च अब तक क्यों नहीं किया गया। हालांकि इस बात की उम्मीद कम ही है कि श्री योगी कभी ऐसे किसी सवाल का जवाब देंगे। उप्र के ग्रामीण स्कूलों में संसाधन जुटें या न जुटें नाम बदलने की कवायद जारी है।

हाल ही में परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर गाजीपुर में उनके पैतृक गांव धामूपुर में बने विद्यालय का नाम बदल दिया गया, गनीमत रही कि इस पर फौरन ही आपत्ति दर्ज हुई और गलती को मानते हुए इसे सुधारा गया। शिक्षा विभाग ने विद्यालय का नाम शहीद वीर अब्दुल हमीद पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय करने का निर्णय लिया है, साथ ही भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं हों, इसके लिए उनके नाम को विद्यालय के अभिलेख में भी दर्ज करने की योजना बनाई गई है। विद्यालय के प्राचार्य ने अब्दुल हमीद के बेटे जैनुल हसन से इस भूल के लिए माफी भी मांग ली है। हालांकि यह महज भूल नहीं है, बल्कि इसमें सांप्रदायिक सोच ही नजर आ रही है।

नाम बदलने की सोच रखने वालों को अब्दुल हमीद ही नजर आया होगा, उसके आगे लगे शहीद का दर्जा देखने की जहमत नहीं उठाई गई। और अगर इस नाम के साथ परमवीर चक्र विजेता या शहीद का दर्जा न भी जुड़ा होता, तब भी अब्दुल हमीद नाम पर आखिर तकलीफ क्यों है। वहां पढ़ाई किस तरह की हो रही है, बच्चों को किस तरह भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, असल सवाल तो यही होने चाहिए। लेकिन भाजपा हर मामले में हिंदू-मुसलमान की राजनीति ही ले आती है।

डोनाल्ड ट्रम्प के नाटो से दूरी बनाने के बाद यूरोप की परीक्षा की घड़ी

यूरोप को यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिए अपने सैन्य बल के साथ तैयार रहना होगा, अगर फरवरी के अंत में मार्च तक ट्रम्प-पुतिन की बैठक युद्ध विराम की ओर ले जाने वाले शांति सूत्र पर पहुंचती है। यह स्पष्ट है कि ट्रम्प यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की जल्दी में हैं और वे उसी स्टीमरोलर नीति का पालन करने के लिए दृढ़ हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के अस्सी साल बाद, यूरोप, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप अव्यवस्थित सा हो गया है, क्योंकि आठ दशकों से उनका ट्रान्साटलांटिक सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नये ट्रम्प सिद्धांत के तहत नाटो से संबंधित यूरोपीय देशों की सुरक्षा की गारंटी देने से इनकार कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उनका महाद्वीप की भू-राजनीति पर इतना व्यापक प्रभाव कभी नहीं पड़ा, जितना 2025 में पड़ रहा है।

17 फरवरी को नाटो और यूरोपीय संघ सहित यूरोपीय देशों के नेताओं की आपातकालीन बैठक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी रणनीति बनाने में विफल रही, जिसमें यूरोपीय देशों, विशेष रूप से नाटो को अमेरिका पर निर्भर हुए बिना अपनी रक्षा प्रणाली के बारे में सोचना पड़ रहा है, जो 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से पिछले 75 वर्षों से एक रक्षा निकाय के रूप में चलन में है। नाटो की स्थापना अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुई थी, जिसमें पश्चिमी यूरोप नाटो के हिस्से के रूप में अमेरिका के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था। तब से यूरोप में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें 1991 में सोवियत संघ का पतन और 1991 के बाद सोवियत राज्य से अलग होकर कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शामिल है। यूक्रेन उन राज्यों में से एक था। 24 फरवरी, 2022 से शुरू होने वाले यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को इस सप्ताहांत तीन साल पूरे हो रहे हैं और इसी सप्ताह, मंगलवार 18 फरवरी को, रूस के विदेश मंत्रियों और अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के रियाद में यूरोप और यूक्रेन के प्रतिनिधित्व के बिना मुलाकात की। यूरोपीय देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबंधित बहिष्कारों का कड़ा विरोध किया, लेकिन बैठक उनके बिना ही चली। राष्ट्रपति ट्रम्प भी नाटो या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की के विचारों को ध्यान में रखे बिना, अपनी शर्तों पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के साथ आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय नेताओं की सोमवार को पेरिस बैठक में यूक्रेन पर आने वाली वार्ता में यूरोपीय नेताओं की भागीदारी की मांग की गयी थी, लेकिन ट्रम्प ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पहले राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति जेलेन्स्की को बुलाया जायेगा। इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि यूरोपीय नेताओं को अनुवर्ती बैठकों में भी आमंत्रित किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प केवल राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करके अनिच्छुक यूरोपीय देशों पर युद्धविराम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प के सलाहकारों और खुद ट्रम्प ने पहले ही इशारा कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बारे में भूलना होगा और राष्ट्रपति जेलेन्स्की को क्रीमिया पर भी अपना दावा छोड़ना होगा, जिस पर अब रूस का कब्जा है। कुल मिलाकर, वार्ता में अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों के मुद्दे को उठाया जा सकता है, जहां मामूली क्षेत्रीय समायोजन पर बातचीत की जा सकती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन द्वारा बुलाई गयी पेरिस में सोमवार की बैठक में, यूरोपीय नेताओं ने तीन वास्तविकताओं को स्वीकार किया रूस पहला, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका और यूरोप अब उन मूल्यों को साझा नहीं करते हैं, जो 1945 से ट्रांसअटलांटिक गठबंधन का आधार रहे हैं। दूसरा, यूरोप अब अपने बचाव के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। तीसरा, यूक्रेन पर अमेरिकी नीति का सवाल। अमेरिकी योजना पर यूरोपीय देशों को अमेरिका द्वारा जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है और अमेरिका को यूरोप को बातचीत की मेज पर आमंत्रित करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि इस समय ट्रम्प की चुनौती का सामना करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होना चाहिए।

बैठक में यूरोपीय सुरक्षा गारंटी के आकलन और रक्षा के लिए अपने स्वयं के धन के आधार पर देशों द्वारा इसे किस हद तक संभव बनाया जा सकता है, इस पर तीखे मतभेद देखे गये। यूक्रेन की युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी पर भी मतभेद थे। मैक्रोन ने पिछले साल यूक्रेन में एक संभावित यूरोपीय शांति सेना की संभावना का उल्लेख किया था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रविवार को कहा कि ब्रिटेन जमीन पर सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। स्वीडन ने सोमवार को इस कदम का समर्थन किया।

सदन में पेश किया गया आठ लाख आठ हजार 736 करोड़ का बजट

लखनऊ। यूपी सरकार का बजट गुरुवार को पेश किया गया। ठीक 11 बजे वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया।

वित्तमंत्री ने सर्वोपेक्षित बातें

इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा—कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ, अवस्थापना, उद्योग, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएँ, ऊर्जा, पूँजी निवेश आदि चिन्हित करते हुये सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की गई है।

प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

सुचा— नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ यूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिये सत्त विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिये दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केन्द्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2022-2023 तक की अवधि के लिये राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी (फंट रनर) राज्य की श्रेणी में रखा गया है।

समेकित षफिस्कल हेल्थ इन्डेक्स जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 था, 2022-2023 में बढ़कर 45.9 हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूँजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा।

इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा।

सामाजिक क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में 27 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 9 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत भी पूँजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय कुल व्यय का 4.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2022-2023 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था।

प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है।

राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गयी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य



यूपी के बजट से क्या कुछ मिला आपको

बिजली के लिए

साल 2017 के पहले प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। न छात्रों को पढाई के लिए बिजली मिलती थी, न ही किसानों को सिंचाई के लिए। अस्पतालों और औद्योगिक इकाइयों को बिजली नहीं मिलती थी। गर्मियों में पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रहती थी। रातों में शहर के शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोगों के घरों में रोशनी है, गर्मियों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध है।

हमारी सरकार ने इस भावना के साथ कार्य किया है— ष्जामते जिन्दगी की कसम है हमें, जरें—जरें में महफिल सजा देंगे हम, तेरे दीवारो—दर जगमगा देंगे हम।

साल 2024-2025 में माह दिसंबर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे 36 मिनट, जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना 3953 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित है।

यह परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कोल इंडिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है।

परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपये अनुमानित है। परियोजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरोठा जनपद झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है।

परियोजनाके लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है, इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएँ भी उत्पन्न होती हैं।

प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है।

योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बिन्दु में इस सम्मानित सदन के समक्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत एवं 11.6 प्रतिशत रहा जो देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष महाराष्ट्र के उपरान्त देश में सर्वाधिक है।



स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।

पी०आर०डी० स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार ६ स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।

अप्रेन्टिस योजना के अन्तर्गत अब तक 2.54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में योजित किया गया।

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-2025 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गयी तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ।

निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 59,64,048 रोजगारों का सृजन हुआ।

स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई०सी०टी०लेब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनायी जा रही है।

नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जायेगा।

इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1 प्रतिशत रहा जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2 प्रतिशत रहा, जब कि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10 प्रतिशत रहा।

स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई०सी०टी०लेब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है।

आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनायी जा रही है।

नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जायेगा।

इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के युवाओं को विशेष तोहफा

इनोवेशन दिवस के अवसर पर यू० पी० स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश में

खादी एवं ग्रामोद्योग

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनाएँ हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे स्थापित होने वाले नये उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हे 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपये के व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क एवं फ्लाईओवर के लिए

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरणसुदृढीकरणनिर्माण की योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरणसुदृढीकरण कार्य हेतु 2900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण हेतु 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिये 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

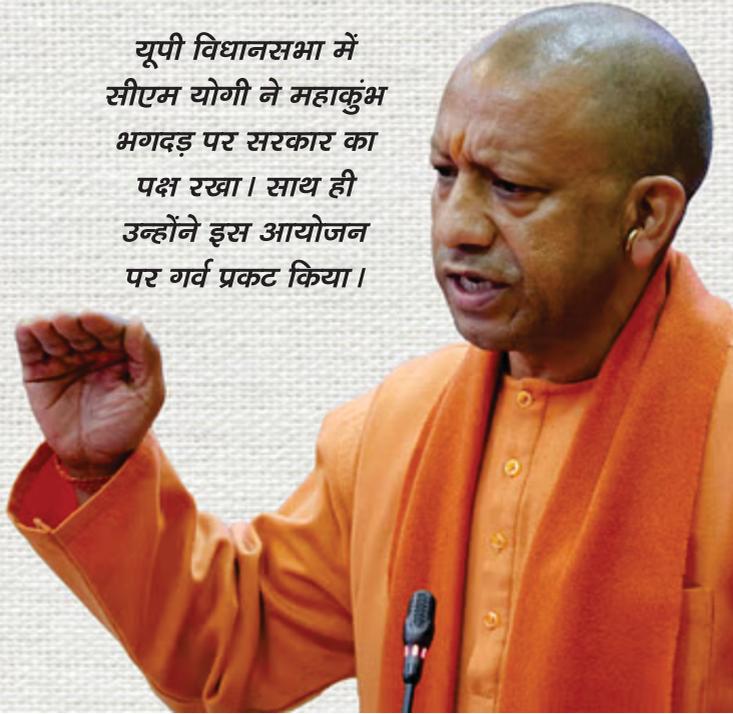
शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

औद्योगिक ६ लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरणसुदृढीकरणनिर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण ६ मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्य एवं सौन्द्यीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

महाकुंभ पर बोले योगी ऐसा आयोजन कराना अपराध तो बार-बार कराएंगे, बताई भगदड़ की वजह



यूपी विधानसभा में
सीएम योगी ने महाकुंभ
भगदड़ पर सरकार का
पक्ष रखा। साथ ही
उन्होंने इस आयोजन
पर गर्व प्रकट किया।

लखनऊ। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष की ओर से बार-बार उठाए जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को लेकर शुरुआत से ही सपा सवाल उठा रही है, मानो जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। सपा की नजर में अगर महाकुंभ का आयोजन अपराध है तो हम ऐसा अपराध बार-बार करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया। योगी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हमने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। भगदड़ के गुनहगार चाहे कोई भी हो और कितनी भी बड़ी पहुंच वाला होगा, बख्शा नहीं जाएगा। वह कहीं भी छिपा होगा, बचेगा नहीं। विधानसभा में सपा के डॉ. आरके वर्मा ने महाकुंभ का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने धार्मिक आयोजन को इवेंट बनाने का प्रयास किया और वीआईपी कल्चर के चलते कुप्रबंधन से हादसा हुआ। उन्होंने सरकार से पोर्टल पर लापता लोगों के बारे में सूचना दर्ज कराने की सुविधा देने की मांग की। सपा के ही डॉ. संग्राम सिंह यादव और कांग्रेस की अराधना मिश्रा मोना ने भी महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इस पर सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने महाकुंभ की आलोचना के लिए सपा सदस्यों को आईना दिखाते हुए कहा कि रामायण की प्रति जलाने वाले महाकुंभ की महत्ता क्या जानें।

सीएम योगी-महाकुंभ भगदड़ को लेकर
सीएम ने साफ की स्थिति, बताया कितने
हुए थे घायल, मौत का दिया आंकड़ा

योगी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हमने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। भगदड़ के गुनहगार चाहे कोई भी हो और कितनी भी बड़ी पहुंच वाला होगा, बख्शा नहीं जाएगा। वह कहीं भी छिपा होगा, बचेगा नहीं। विधानसभा में सपा के डॉ. आरके वर्मा ने महाकुंभ का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने धार्मिक आयोजन को इवेंट बनाने का प्रयास किया और वीआईपी कल्चर के चलते कुप्रबंधन से हादसा हुआ। उन्होंने सरकार से पोर्टल पर लापता लोगों के बारे में सूचना दर्ज कराने की सुविधा देने की मांग की।

लखनऊ में प्रापर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

शादी में विवाद हुआ, फोन कर
दुकान पर बुलाया और गाली देते
हुए फायर कर दिया

लखनऊ। प्रापर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार देर रात काकोरी थाना के बेहटा गांव में हुई। मृतक की पहचान 43 साल अंकित लोधी के रूप में हुई है। दरअसल, गांव में एक शादी में पहले दो गुटों में विवाद हुआ। इसी बात को लेकर कुछ देर बाद प्रापर्टी डीलर अंकित के जीजा ने उसे पान की दुकान पर बुलाया। यहां दूसरे गुट के बदमाशों ने गाली देते हुए फायर झोंक दिया। हमलावरों में 4 युवक शामिल थे। फायरिंग में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।



यह फोटो मृतक अंकित लोधी की है
जिसकी गोली मारकर हत्या की गई।

जौनपुर में बड़ा हादसा... हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहन



नौ श्रद्धालुओं की मौत, 32 घायल

जौनपुर। जौनपुर जिले में गुरुवार की भोर में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में नौ दर्शनार्थियों की मौत हो गई। जबकि 32 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग

731 के सरोखनपुर अंडर पास पर भीषण हादसा हुआ। दो वाहनों की भिड़ंत में टाटा सूमो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी घटना के समय एक बस ट्रेलर से भिड़ गई। इस हादसे में बस में सवार तीन लोगों की मौत हो

गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद एक और श्रद्धालु की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। ऐसे में मरने वालों की संख्या नौ हो गई है। बस में सवार सभी लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं, जो

चित्रकूट से प्रयागराज होकर वाराणसी दर्शन के बाद अयोध्या जा रहे थे। वहीं सूमो सवार सभी झारखंड के हैं, जो वाराणसी से अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे।

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना उस वक्त हुई जब बस में सवार दर्शनार्थी सो रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ बस ट्रेलर से भिड़ी तो दर्शनार्थी हैरान रह गए। सोने के कारण कई लोग अचानक झटके से चोटिल हुए। वहीं आगे बैठे दर्शनार्थी बुरी तरह घायल हो गए। वहीं सूमो में सवार दर्शनार्थी भी आधी नींद में ही थे। घटना के बाद आनन-फानन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है।



सावधान- नाचते गाते और एक्सरसाइज करते-करते हार्ट अटैक से क्यो हो रही मौतें, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलतियां

आगरा। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही सीधा मौत का डर दिखाई देता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें 20 से 30 साल के युवा हार्ट अटैक में अपनी जान गवां रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जब इस बारे में विशेषज्ञों से बात की गई, तो जानें उनका क्या कहना है... नृत्य करते, खेलते-कूदते या व्यायाम करते हार्ट अटैक। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें 20-30 की उम्र के युवाओं की जान जा रही है। इसके लिए चिकित्सक बाहर का खाना, देर रात तक जागना और तनाव को बड़ी वजह मान रहे हैं। चिकित्सकों का मानना है कि जो लोग सप्ताह में 4-5 बार बाहर का भोजन कर रहे हैं उन्हें हार्ट अटैक का तीन गुना ज्यादा खतरा है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार गुप्ता बताते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार 82 फीसदी लोग अपने नौकरी-कार्य के चलते तनाव में हैं। 76 फीसदी चिंतित रहते हैं और 56 फीसदी 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं। बीते 5 सालों में बाहर के खाने और फास्ट

फूड का चलन तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। दरअसल, रेस्तरां, स्टॉल समेत अन्य में भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए तेल बार-बार गर्म किया जाता है, जिसके चलते ये जहर के समान हो जाता है। इसमें पकी सामग्री के इस्तेमाल से हृदय की नस संकुचित होने लगती हैं। अगर सप्ताह में कोई 4-5 बार बाहर का भोजन करता है तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी तीन गुना बढ़ जाता है। स्वस्थ दिनचर्या और संतुलित खान-पान से हृदय रोग का खतरा काफी कम हो जाता है।
एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी में हर तीसरा मरीज युवा
एसएन मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के डॉ. सौरभ नागर ने बताया कि ओपीडी में 50 फीसदी मरीज युवा हैं। कैंथ लैब में एंजियोग्राफी-एंजियोप्लास्टी करवाने वाले हर तीसरे मरीज की उम्र भी 30 साल से कम है। इसकी बड़ी वजह देर रात तक जागना, कंप्यूटर-मोबाइल चलाना, नौकरी-करियर का तनाव और धूम्रपान-एल्कोहल है। इससे हृदय रोग पनप रहा है।



बढ़ रहे हैं हार्ट
अटैक के मामले
क्या है वजह?

इन बातों का रखें ख्याल

- धूम्रपान-एल्कोहल से बचें। पास में कोई धूम्रपान करे तो मास्क लगा लें।
- बाजार के भोजन, फास्ट फूड की लत न लगाएं। घर का भोजन करें।
- मोटा अनाज, दाल, हरी सब्जी, सलाद, फल अधिक खाएं।
- रात 8 बजे से पहले भोजन कर लें, 7-8 घंटे की नींद लें।
- रोजाना 45 मिनट तेज गति से चलें, पैदल चलने की आदत डालें।
- महिलाएं घरेलू कार्य करें, योग, ध्यान करें।

योगी सरकार का बजट

किसानों और खेतिहरों
को ये तोहफे

गन्ना किसानों को राहत

सोलर पंप से फसल उत्पादन बढ़ाने
तक सरकार का प्लान रेडी

लखनऊ। खेतों में सोलर पंप लगाने से लेकर फसल उत्पादन बढ़ाने तक के लिए सरकार का प्लान रेडी है। साथ ही गन्ना किसानों को भी राहत मिली है। आगे पढ़ें और जानें बजट में किसानों को क्या मिला? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 9वां बजट गुरुवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट में कई बड़े एलान किए हैं। यूपी सरकार ने इस बजट में किसानों का भी विशेष ध्यान रखा है। किसानों के लिए कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए कई एलान किए हैं। आगे बिंदुवार पढ़िए बजट में किसानों को क्या मिला...

कृषि क्षेत्र में-

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुआई का क्षेत्र बढ़ाने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है। इसके लिए 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार क्षेत्र में-

कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा कृषकों को प्रभावी परिणाम उपलब्ध कराने के लिए पांच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं।

कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए-

झांप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय औद्योगिक/खाद्य/गन्ना मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में-

वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना की खेती और चीनी मिलें, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिपराइच चीनी मिल में 60 केएलपीडी क्षमता की आसवानी की स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बंद पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कामप्लेक्स की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।



चार एक्सप्रेसवे, छात्राओं को फ्री स्कूटी,
सैनिक स्कूल खुलने का ऐलान
यूपी बजट में तोहफों की बरसात

लखनऊ। प्रदेश सरकार का बजट पेश किया गया। बजट के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि हमने अपने बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि समाज के सभी वर्गों का समान विकास हो। प्रदेश की जो इमेज बनी हुई है उसमें बदलाव आए। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ रुपये से अधिक (8,08,736.06 करोड़ रुपये) का है। वर्ष 2024-25 के बजट के सापेक्ष इसमें 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के बजट के आकार में यह बढ़ोत्तरी राज्य के सामर्थ्य के अनुरूप है। यह बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम ने कहा कि कुल व्यय में 02 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जी०डी०पी० 12.89 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ये प्रमुख बातें

बजट में व्यय की नई मदों हेतु 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान। अवस्थापना विकास के लिये 01 लाख 79 हजार 131 करोड़ 04 लाख रुपये प्रस्तावित।

इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिये 61,070 करोड़ रुपये से अधिक, सिंचाई के लिये 21,340 करोड़ रुपये से अधिक, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिये लगभग 24 हजार करोड़ रुपये, नगर विकास के लिये 25,308 करोड़ रुपये से अधिक, आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 7,403 करोड़ रुपये से अधिक तथा नागरिक उड्डयन के लिये 3,152 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

शिक्षा क्षेत्र के लिये 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित। (कुल बजट का 13) शिक्षा पर इतना व्यय करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है।

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुधन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिये कुल लगभग 89,353 करोड़ रुपये प्रस्तावित। (कुल बजट का 11 प्रतिशत)

चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये 50,550 करोड़ रुपये से अधिक का

प्रावधान। (कुल बजट का 6 प्रतिशत) प्रदेश के सभी होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक एवं मानदेय के आधार पर कार्य करने हेतु वाले कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा।

बजट की प्रमुख बातें

श्री बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा-वृन्दावन कॉरिडोर के निर्माण व भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

जनपद मीरजापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथ एवं जन सुविधाओं के विकास हेतु भूमि खरीद व निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

चित्रकूट में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का है बजट

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश

योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध

और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को शआदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	2024-25	2025-26
अनुमानित बजट	736643.71	810984.18
राजस्व प्राप्ति	606802.40	681172.33
कर राजस्व	488902.57	552460.21
स्वयं के कर राजस्व	270086.00	305197.18
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	218816.84	274263.03
केंद्र से अनुदान	93464.72	102811.19

नोट-आंकड़े करोड़ रुपए में हैं।

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में योगी सरकार करेगी मदद

बजट में 200 करोड़ का प्रावधान

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंस्ट्रिट्रियल कारीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये का प्रविधान भी सरकार ने किया है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 9.5 हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

लखनऊ। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए योजनाओं की सौगात दी है। इसके तहत दलित व पिछड़े समाज के लोगों के लिए घोषणाओं का एलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। गुरुवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने वृद्धजन, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है।

बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को दी गई प्राथमिकता

बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

वृद्धजनों के पेंशन के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था

योगी सरकार ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों

और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्थाधिकसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस योजना के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

इससे प्रदेश के लाखों वृद्धजनों और किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए षुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को और मजबूती दी गई है, जिसके लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में भारी निवेश किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसी योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भी शिक्षा को लेकर सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। इनके लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 6 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री

जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान षीएम-जनमन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास किया जाना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतुष्ट किया जाना है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम

योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए 1424 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छोटे बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री-स्कूल रेडीनेस के लिए 18 मण्डलीय जनपदों में श्वचपन डे केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विशेष बजट का आवंटन

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए इस बजट में 1998 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे समाज के इस वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।



8105
करोड़ रुपये
गरीब बजुर्गों को
पेंशन के लिए

5064
करोड़ रुपये
छात्रवृत्ति के लिए



**एक बाइक पर थे 5 सवार
आगे जा रहे वाहन से हुई टक्कर
4 की मौत और 1 गंभीर घायल**



कानपुर में युवक की हत्या

- आरोपियों ने शव घर में घसीटकर किया बंद
- पांच घंटे की मशक्कत के बाद दिया शव
- बेबस दिखे पुलिस के बड़े अधिकारी
- 10 थानों की फोर्स और दो कंपनी पीएसी

बीच रास्ते युवक का कत्ल...

लाश को घसीटकर घर में किया बंद, बेबस दिखे अधिकारी, रवि यादव हत्याकांड की कहानी

कानपुर। पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने हत्या कर शव को घसीटकर घर में बंद कर लिया। पुलिस ने पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव कब्जे में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आक्रोशित ग्रामीणों के सामने पुलिस अधिकारी बेबस दिखे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है।

यहां सजेती के दौलतपुर गांव में बुधवार को घर के बाहर बैठे युवक ने पुरानी रंजिश में पड़ोसी की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव घसीटकर अपने घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी का घर घेर लिया। सूचना पर 10 थानों की फोर्स और दो कंपनी पीएसी संग मौके पर पहुंचे डीसीपी ने खुद मोर्चा संभाला। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी तीन भाइयों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। तनाव को देखते हुए गांव में एक कंपनी पीएसी और दो एसएचओ को फोर्स के साथ तैनात किया गया है।

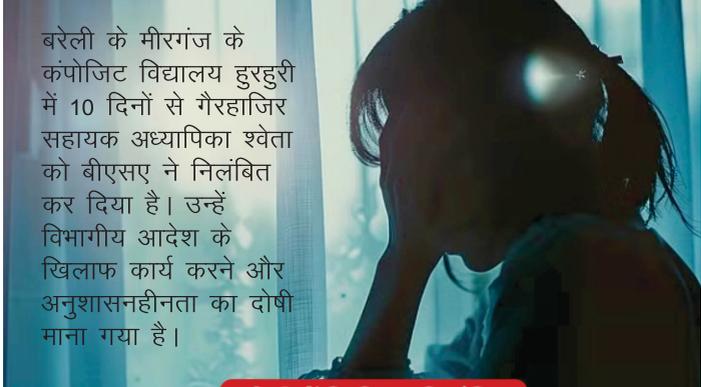
दौलतपुर गांव निवासी रवि यादव (22) का गांव के ही मधुराम त्रिपाठी से परिवार की एक युवती से बातचीत को लेकर विवाद

चल रहा था। रवि को शक था कि गांव का रहने वाला नमन गुप्ता मधुराम की शह पर उसकी बहन से बात कर रहा था। इस बात को लेकर मधुराम और रवि में रंजिश चल रही थी।

रवि की गोली मारकर हत्या
बुधवार दोपहर करीब तीन बजे रवि बाइक से जानवरों का चारा लेने के लिए खेत जा रहा था। तभी घर के बाहर खड़े मधुराम और उसके भाइयों शुभम व मयंक की रवि से कहासुनी हो गई। गुस्से में आए मधुराम ने रवि की कनपटी पर पिस्टल लगाकर गोली मार दी। उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

रवि की लाश को घर में घसीटा
इसके बाद मधुराम ने भाइयों की मदद से रवि के शव को घर के अंदर घसीट लिया। इधर रवि की हत्या की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मधुराम के घर को घेर लिया।

इधर, यादव बहुल गांव में हुई हत्या की सूचना पर डीसीपी साउथ आशीष श्रीवास्तव, एडीसीपी महेश कुमार, एसीपी रंजीत कुमार भारी फोर्स संग पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह हटने को तैयार नहीं थे। करीब पांच घंटे की मान मनौवल के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया।



बरेली में शिक्षिका निलंबित
**ब्लैकमेल कर युवक से
ऐंठे 35 लाख रुपये**

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें महाराज वृंदावन हंस रहे हैं और उन्हें हंसा रही थीं जोजो और जानी की जोड़ी।



**हंस-हंसकर लोटपोट
हुए संत प्रेमानंद
इस कला के हुए मुरीद**



**पुलिस की वर्दी देख इस
कदर डर गई युवती...
13 लाख रुपये गवांए**

नोएडा। साइबर अपराधियों ने नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत शाहगंज की युवती को 4 दिन डिजिटल अरेस्ट किया। आधार कार्ड से क्रूरियर में प्रतिबंधित ड्रग और फर्जी पासपोर्ट भेजने का आरोप लगाकर धमकाया। सीबीआई का फर्जी नोटिस भी भेजा। पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर बात की। खाते में 13.41 लाख रुपये जमा करा लिए। साइबर थाना में केस दर्ज कराया गया है।



**नमो घाट पर तमिल कलाकारों
ने मोहा मव, तस्वीरों में देखें-
मनमोहक नजारा**



करोड़ि एक्टर ने 26 साल छोटी लड़की से किया निकाह

दिमाग और आत्मा से मरा हुआ समाज..

'छावा' फिल्म और महाकुंभ को लेकर अभिनेत्री ने की टिप्पणी

एंटरटेनमेंट डेस्क। हाल ही में अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने 'छावा' फिल्म को महाकुंभ घटना से जोड़कर दर्शकों पर व्यंग्य किया है। इस बात पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'छावा' इस समय सिनेमाघरों में छाई हुई है। इसे लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है, जिसमें वह 'छावा' फिल्म पर दर्शकों की आ रही प्रतिक्रियाओं को लेकर टिप्पणी करते हुए उसे महाकुंभ में हुई घटना से जोड़ते हुए कटाक्ष किया है।

दिमाग और आत्मा से मरा हुआ समाज.

हाल ही में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में वह 'छावा' फिल्म को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं पर लिखती हैं कि लोग 500 साल पहले हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को काल्पनिक फिल्मों के जरिए दिखाए जाने पर क्रोधित हो रहे हैं।

उन्हें महाकुंभ में खराब प्रबंधन की वजह से भगदड़ में हुई मौतों पर कोई क्रोध नहीं आ रहा है। वहां के शवों को बुलडोजर से हटाया गया। ये समाज दिमाग और आत्मा से मरा हुआ है।

एंटरटेनमेंट डेस्क। सुदर्शन फाकिर का नाम उर्दू जानने वालों के लिए नया नहीं है। उन्होंने उन्होंने उर्दू की गजलें, बॉलीवुड के गाने और धार्मिक गाने लिखे हैं। आज उनके जनमदिन के मौके पर उन्हें उनके बारे में। सुदर्शन फाकिर उर्दू के उन चंद शायरों में शुमार होते थे, जो गैर मुस्लिम थे। सुदर्शन फाकिर वही शख्स थे, जिनकी गजलों को गजल गायक जगजीत सिंह ने गाया है। सुदर्शन फाकिर की गजलों को बेगम अख्तर ने भी गाया। सुदर्शन फाकिर ने गजलों के अलावा कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे।

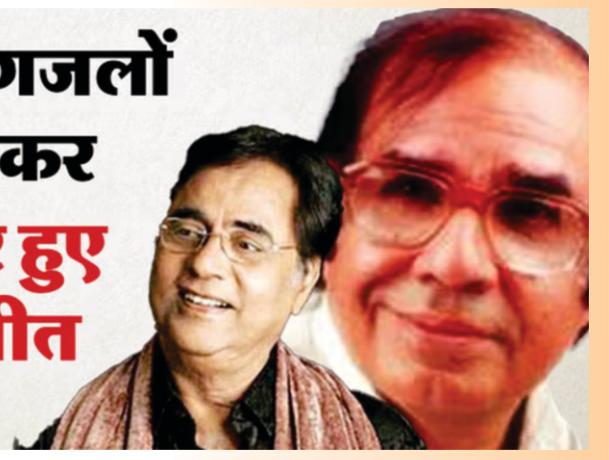
शुरुआत में ही छोड़ दी आपनी छाप

सुदर्शन फाकिर पंजाब के जालंधर में साल 1934 में पैदा हुए। वह अपने कॉलेज के दिनों में शेर व शायरी लिखते थे और झगड़ों में काम किया करते थे। अपने कॉलेज के दिनों में सुदर्शन ने अशद का एक दिन प्ले का निर्देशन किया। मुंबई जाने के बाद सुदर्शन फाकिर ने दूरियां फिल्म का जिंदगी, जिगदी मेरे घर आना जिंदगी गाना लिखा। उन्होंने यलगा र फिल्म के डॉयलॉग लिखे। उनके ये दोनों काम आज भी बहुत मशहूर हैं।

फिल्ममेयर अवार्ड जीतने वाले पहले गीतकार

सुदर्शन फाकिर ने अपने गानों से लोगों का दिल तो जीता ही, उन्होंने बॉलीवुड पर भी राज किया। उन्होंने बरसात के मौसम में, आखिर तुम्हें आना है जैसे गाने लिखे। सुदर्शन फाकिर पहले ऐसे गीतकार थे, जिन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता। सुदर्शन फाकिर ने फिल्मी गानों और गजलों के अलावा धार्मिक गाने हे राम... हे राम लिखा।

जिनकी गजलों को गाकर मशहूर हुए जगजीत



इस मशहूर शायर की गजलें गाकर मकबूल हुए गजल गायक जगजीत सिंह

महाकुंभ में पहुंची विक्की कौशल के साथ काम कर चुकी यह एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क। हाल ही में अभिनेत्री रीवा अरोड़ा महाकुंभ पहुंची थीं। सोशल मीडिया पर इस यात्रा से जुड़ी तस्वीरें साझा करने के पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बाल कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रीवा अरोड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वह महाकुंभ 2025 में अपनी यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरों को लेकर लोगों के निशाने पर आ गई हैं। रीवा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रयागराज से अपनी कुछ सुंदर तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में वह एक पारंपरिक नारंगी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं।

लोगों ने किया ट्रोल

रीवा अरोड़ा ने महाकुंभ के अद्भुत दृश्य को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, एक बार जिंदगी में ऐसा जादू देखना...महाकुंभ का पवित्र दृश्य। हालांकि, इन तस्वीरों को पोस्ट करते ही उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने उनकी तस्वीरों को लेकर आपत्ति जताई। कहना था कि वह एक स्थान पर शूट करवा



रही हैं। एक यूजर ने लिखा, घे फोटोशूट करने की जगह नहीं है। वहीं, कुछ ने उन्हें नौटंकीबाज और क्रिंज तक कहते हुए यह पूछ डाला कि यह सब दिखावा क्या जरूरी है? हालांकि, आलोचनाओं के अलावा कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रीवा अरोड़ा की तस्वीरों की तारीफ भी की। उन्होंने रीवा को सुंदर,शानदार, क्यूट, जैसे शब्दों से भी नवाजा।

कावेरी कपूर एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कावेरी कपूर ने फिल्म बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। डेब्यू मूवी में कावेरी के काम को सराहा जा रहा है। शेखर कपूर और सुचित्रा कृष्णमूर्ति की लाडली बेटी ने पहली फिल्म से ही लाइमलाइट चुरा ली है। फिल्मी दुनिया के अलावा उनका परिवार पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहता है। अब कावेरी ने अपने माता-पिता के तलाक पर चुप्पी तोड़ी है और बताया कि उस समय उन्हें कैसा महसूस हुआ था।

कावेरी ने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया, तो उनके माता-पिता काफी खुश थे। एक्ट्रेस का कहना है कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि एक बार वह एक्टिंग को आजमाकर जरूर देखें। सुचित्रा अपनी बेटी की पहली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से कावेरी को फिल्म करने के लिए प्रोत्साहित किया था।

माता-पिता के

ईटाइम्स से अलावा एक्ट्रेस से के डिवोर्स का कहा, दोनों के किया जितना हुआ, तो मैं सच है कि हुआ है। सार्वजनिक आप उन ह... बिल्कु

तलाक का क्या असर पड़ा ?

बातचीत में कावेरी कपूर ने फिल्म के माता-पिता के रिश्ते पर भी बात की। सवाल किया गया कि शेखर और सुचित्रा उनके ऊपर क्या असर पड़ा। उन्होंने अलगाव ने मुझे उतना प्रभावित नहीं रिश्ते ने किया। जब उनका डिवोर्स खुश थी। लेकिन, यह बात इससे काफी नुकसान खासकर यह इतना क था और इस वजह से चीजों का सामना करते जिससे एक बच्चे को ल भी निपटना नहीं आता है। इसके कारण मैं एक एडल्ट के तौर पर मेंटल स्ट्रेस से जूझ रही हूं।



भूमि पेडनेकर बोलीं-

पूरी तरह से टूट चुके थे

दिल्ली। भूमि पेडनेकर इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपने करियर में हर रंग की भूमिकाएं की हैं। अपने किरदारों के जरिए महिला मुद्दों को मुखर करने वाली भूमि कई फिल्मों में पत्नी की अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आ चुकी हैं। इन दिनों वे खबरों में हैं अपनी नई फिल्म श्मेरे हसबैंड की बीवी से। इस मुलाकात में पत्नी का रोल निभाने वाली भूमि शादी, विमेन इश्यूज, अपने जीवन के मुश्किल दौर, फिल्म और अपने हीरो अर्जुन कपूर को लेकर खुल कर बातें करती हैं। मुझे लगता है कि आज शादी करने के रीजन अलग हो गए हैं। मैं एक लड़की के नजरिए से बता सकती हूं। ऐसा कहा जाता था कि शादी जल्दी करो क्योंकि आपका भविष्य ही शादी है। अब हुआ ये है कि कई लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, तो अब ऐसा है कि मैं तो पहले से सेटल हूं, तो अब मुझे जो चाहिए, वो कपैनिशनशिप है। जहां तक मेरी बात है, तो मैं शादी में गहरा विश्वास करती हूं मगर मेरा मानना है कि मैं शादी कपैनिशनशिप के नजरिए से करना चाहूंगी।

भूमि पेडनेकर अपनी नई फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी में एक पत्नी की भूमिका निभाने जा रही हैं। इस फिल्म को लेकर और रियल लाइफ में महिला और शादी के मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। अपने गुजरे वक्त को याद कर कहा- हम भावनात्मक रूप से टूटे हुए थे, आर्थिक रूप से टूट चुके थे। हम वाकई पूरी तरह से टूट चुके थे।





बाल-बाल बचे सौरव गांगुली बर्धमान के पास लॉरी के अचानक आगे निकलने से हुआ हादसा

सौरव गांगुली ने बायोपिक का किया खुलासा
राजकुमार राव निभाएँगे मुख्य भूमिका

राजकुमार राव बनेंगे आन-स्क्रीन क्रिकेट के दादा
सौरव गांगुली ने किया खुद खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी बायोपिक के बारे में बात की और बताया कि बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव फिल्म में उनकी भूमिका निभाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि राजकुमार राव भूमिका निभाएंगे।

सौरव गांगुली ने कहा, मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजकुमार राव भूमिका निभाएंगे...लेकिन तारीखों का मुद्दा है... इसलिए इसे स्क्रीन पर आने में एक साल से अधिक समय लगेगा।

ऐसा रहा है अंतरराष्ट्रीय करियर

गौरतलब हो कि पूर्व कप्तान ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे खेले हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सभी फॉर्मेट में 18,575 रन बनाए हैं। कोलकाता के राजकुमार बाद में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के अध्यक्ष बने और बाद में पिछले साल अक्टूबर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

2008 में लिया संन्यास

उन्होंने भारत को 21 टेस्ट जीत और साल 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने इस खिलाड़ी ने बीसीसीआई की तकनीकी समिति में भी काम किया और भारतीय महान खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण के साथ क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। गांगुली ने 2008 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया और इस दौरान उन्होंने 18,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए।

कार का हुआ एक्सीडेंट

बात दें कि हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट तब हुआ जब वो अपने काफिले के साथ दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से बर्धमान जा रहे थे। सौरव गांगुली इस हादसे में बाल-बाल बच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी काफिले के बीच में एक लॉरी आ गई, जिसके चलते कारों को इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी। हालांकि, राहत की बात ये रही कि इस हादसे में न तो दादा को कोई चोट पहुंची और न ही उनके किसी साथी को।

क्रिकेट जगत पर अपने बल्ले का दम दिवा चुके सौरव गांगुली की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। क्रिकेट के महाराजा कहे जाने वाले सौरव गांगुली की बायोपिक बन रही है। बालीवुड एक्टर आन-स्क्रीन सौरव गांगुली बनेगा उसका नाम सामने आ गया है। खुद पूर्व भारतीय कप्तान ने इसकी घोषणा की है। सौरव गांगुली ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है।



आयरलैंड के खिलाफ जीत का लक्ष्य लेकर उतरेगी भारतीय टीम
हरमनप्रीत और हार्दिक पर रहेगी नजर

खेल। भारतीय टीम हालांकि जर्मनी के खिलाफ 1/4 से हार गई लेकिन अगले मैच में वह विश्व में चौथे नंबर की टीम को 1दू0 से पराजित करने में सफल रही। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने चोट से उबरने के बाद वापसी की थी। लेकिन विश्व में पांचवें नंबर की भारतीय टीम विश्व में दसवें नंबर की आयरलैंड की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर प्रतिबद्ध है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम शुक्रवार को यहां एफआईएच प्रो लीग में जब आयरलैंड का सामना करेगी तो उसका लक्ष्य अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखना और पेनल्टी कॉर्नर को भुनाना होगा। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी तक उतार चढ़ाव वाला रहा है। उसे टूर्नामेंट के शुरू में स्पेन से 1/3 हार का सामना करना पड़ा था लेकिन उसने इसी टीम को अगले मैच में 2/0 से पराजित करके अच्छी वापसी की थी।

भारतीय टीम हालांकि जर्मनी के खिलाफ 1/4 से हार गई लेकिन अगले मैच में वह विश्व में चौथे नंबर की टीम को 1दू0 से पराजित करने में सफल रही। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने चोट से उबरने के बाद वापसी की थी। लेकिन विश्व में पांचवें नंबर की भारतीय टीम विश्व में दसवें नंबर की आयरलैंड की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर प्रतिबद्ध है। कप्तान हरमनप्रीत का मानना है कि टीम को अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आगामी मैच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम इन मैच में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक मैच में सुधार की गुंजाइश होती है। हम जानते हैं कि आयरलैंड हमारे सामने कड़ी चुनौती पेश करेगा। मले ही उनकी टीम रैकिंग में हमसे पीछे है लेकिन उसकी टीम कभी हार नहीं मानती और अपने प्रदर्शन से विरोधी टीम को हैरानी में डाल सकती है। इसलिए हम उन्हें कमजोर करके नहीं आंक सकते हैं।

भारतीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई खिताब जीता स्वर्ण पदक जीतने में रहे सफल



आडवाणी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी और स्वर्ण पदक जीता।



स्पोर्ट्स डेस्क। आडवाणी की जीत से उनके पुरस्कारों की सूची में एक और इजाफा हुआ। अब उनके नाम पांच एशियाई स्नूकर खिताब (15-रेड, 6-रेड और टीम प्रारूप में) के साथ नौ एशियाई विलियर्ड्स खिताब हैं। भारतीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में 14वां खिताब जीत लिया। आडवाणी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी और स्वर्ण पदक जीता। आडवाणी ने इंदौर में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के कुछ ही दिन बाद यह खिताब हासिल किया जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि वह देश के सबसे प्रतिष्ठित क्यू खिलाड़ी हैं।

पुरस्कारों की सूची में हुआ इजाफा

आडवाणी की जीत से उनके पुरस्कारों की सूची में एक और इजाफा हुआ। अब उनके नाम पांच एशियाई स्नूकर खिताब (15-रेड, 6-रेड और टीम प्रारूप में) के साथ नौ एशियाई विलियर्ड्स खिताब हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक (2006, 2010) भी जीते हैं। इस जीत से वह एक अभूतपूर्व उपलब्धि के ओर करीब पहुंच गए हैं जिसमें एक ही कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीतना शामिल है। विलियर्ड्स में यह उपलब्धि हासिल करने

के बाद अब अगर वह स्नूकर में ऐसा कर लेंगे तो वह दोनों स्पर्धाओं में ऐसा करने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे।

ईरान के अमीर सरखोश के खिलाफ फाइनल चैंपियन के बीच मुकाबला था। पूर्व एशियाई और विश्व आईबीएसएफ 6-रेड स्नूकर चैंपियन सरखोश ने शुरुआती बढ़त हासिल की। लेकिन दबाव में अपने संयम के लिए मशहूर आडवाणी ने शानदार तरीके से जवाब दिया। आडवाणी ने 93 और 66 के ब्रेक से मैच पर नियंत्रण कर लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

जीत के बाद आडवाणी ने कहा, 14वां एशियाई खिताब जीतना बहुत ही विशेष है, खासकर स्नूकर में। यह एक कठिन टूर्नामेंट रहा है और मैं अपने संग्रह में एक और स्वर्ण जोड़कर रोमांचित हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस लय को आगे भी जारी रखूंगा और भारत को गौरवान्वित करता रहूंगा।

इस जीत ने क्यू स्पोर्ट्स के इतिहास में उनकी जगह को और भी मजबूत कर दिया है। चूंकि वह इस साल के अंत में होने वाली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि क्या वह अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

44 साल की उम्र में वीनस विलियम्स की कोर्ट पर वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क। सात बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन वीनस ने 19 मार्च, 2024 को मियामी ओपन के पहले दौर में हार के बाद किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है।

वीनस विलियम्स को अगले महीने इंडियन वेल्स में होने वाले बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है जो इस 44 वर्षीय खिलाड़ी का पिछले एक साल में पहला टूर्नामेंट होगा।

सात बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन



वीनस ने 19 मार्च, 2024 को मियामी ओपन के पहले दौर में हार के बाद किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। वीनस ने पहली बार 1994 में

इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में भाग लिया था। उनके नाम पर विंबलडन में पांच और अमेरिकी ओपन में दो एकल खिताब दर्ज हैं। वीनस ने इसके साथ ही अपनी छोटी बहन सेरेना के साथ मिलकर 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी जीते हैं। जिन अन्य खिलाड़ियों को वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है उनमें दो बार की विंबलडन चैंपियन पेट्रा क्वितोवा भी शामिल हैं जो अपने पहले बच्चे को जन्म देने के कारण 15 महीने तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रही हैं।

दी नैक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक
बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन
ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा
हुसैनिया बिल्डिंग बक्सिपुर
गोरखपुर से मुद्रित एवं 665
बी गंगा टोला, निकट
जानकी बिल्डिंग मैटेरियल
बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर
से प्रकाशित। पिन:- 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार

मो. नं. 7307180148, 9170772370

Email- thenextpost01@gmail.com

नोट:- समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद
गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगा।

कुछ भी गारंटी नहीं है, भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर युवराज सिंह का बड़ा बयान, मैच को बताया खास

युवराज सिंह ने जियो हॉटस्टार के ग्रेटेस्ट राइवलरी रिटर्न्स शो में कहा कोई भी प्रारूप हो भारत-पाकिस्तान का खेल हमेशा फाइनल जैसा लगता है- चाहे वह गुप मैच हो सेमीफाइनल हो या चैंपियनशिप हो। दबाव बहुत ज्यादा होता है। आप हारना नहीं चाहते क्योंकि इससे टूर्नामेंट का माहौल बनता है। जीतने से गति और आत्मविश्वास बढ़ता है। मैच बेहद खास है।

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रविवार 23 फरवरी को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच अक्सर होने वाली लड़ाइयों के कारण इस मुकाबले को काफी चर्चा हो रही है। पिछली बार दोनों टीमों में जून में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच में भिड़ी थीं। भारत ने एक करीबी मुकाबले में पाकिस्तान को छह रन से हराया था। दोनों के मैच से पहले भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। युवराज सिंह उन क्रिकेटर्स में से एक रहे हैं जो भारत-पाकिस्तान के बीच हुए कई रोमांचक मुकाबलों का हिस्सा रहे हैं। चाहे वह टी20 विश्व कप 2007 का फाइनल हो, विश्व कप 2011 का सेमीफाइनल हो या चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल, हर इवेंट में यह ऑलराउंडर सबसे आगे रहा। प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, जब दोनों



देश मिलते हैं तो कुछ भी गारंटी नहीं होती, हर मैच फाइनल जैसा होता है।
कुछ गारंटी नहीं है
युवराज सिंह ने जियो हॉटस्टार के ग्रेटेस्ट राइवलरी रिटर्न्स शो में कहा, कोई भी प्रारूप हो, भारत-पाकिस्तान का खेल हमेशा फाइनल जैसा लगता है- चाहे वह गुप मैच हो, सेमीफाइनल हो या चैंपियनशिप हो। दबाव बहुत ज्यादा होता है। आप हारना नहीं चाहते क्योंकि इससे टूर्नामेंट का माहौल बनता है। जीतने से गति और आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, तो हमने पहले गेम में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन उन्होंने हमें फाइनल में हरा दिया था। इसलिए, कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन इतने बड़े मंच पर जीत के साथ शुरुआत करना, जब पूरी दुनिया देख रही हो, बहुत महत्वपूर्ण है।